(ग) क्या सहायता राशि अपर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त जारी करने/भुगतान करने संबंधी मानदंडों में संशोधन करने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें हाल की बात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 648.00 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता को दर्शाया गया है । इसमें प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 82.75 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है । राहत व्यय वित्तपोषण की मौजूदा स्कीम के आधार पर, आपदा राहत निधि में वर्ष 1994-95 के लिए सम्पूर्ण केन्द्रीय अंश की 63.75 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को दे दी गई है ।

(ग) से (ङ) दसवें वित्त आयोग ने भी राहत व्यय वित्त पोषण की मौजूदा स्कीम की समीक्षा की है । राज्य सरकार ने इस मामले पर अपना ज्ञापन सीधे आयोग को प्रस्तुत किया था ।

Agricultural Costs and Prices Commission

1512. SHRI BHUPINDER SINGH MANN; Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the terms of reference of the Agricultural Cost and Prices Commission (ACPC);

(b) whether Government consider to amend the terms of reference of the commission to match the liberalization policies of Government ;

(c) if so, the details thereof and if *not,* the reasons therefor ;

(d) whether Government would make public the detrils of calcu'ations of minimum support price of agricultural produce: and

(e) if so, by when and if not, tb? reason renftr, 7

THE MINISTER OF STATE TN THE RICUTURE (SHRI S. :NA KUMAR) : (a) The terms of reference $_0$f f)$_{ie}$ Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) are given in the enclosed Statement (55M below)

(b) and (c) While formulating its recommendations on Price Policy the CACP apart from making a comprehensive overview of the the entire structure of the economy of a particular comrhodity considers a number of important factors i.e., cost of production, changes in input prices, input/output price parity, trends in market prices, demand and situation, inter-crop price parity, effect on industrial cost' structure, effect of general price level, effect on cost of living, international market price situation and parity between prices paid and prices received by as, the current policies of the mem including those of liberalization are kepi in view.

(d) and (e) The Reports o^r the CACP confining fll relevant data are made public.

Statement

The terms of reference of the Commission for Agricultural Costs and Prices are as under :—

1. To advif e on the price policy of paddy, rice whent, jowF.r, bijra, maize, ragi, barley, gram, tur, moong, urad, sugarcane, groundnut, soyabean, sunflowerseed, rapeseed and mustard, cotton, jute, tobacco and such other commodities as the Government may indicate from time to time with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the nersne^tive of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer.

2. While recommending the price policy and relative price structure, the commission may keep in view the following :

(i) The need to provide incentive fo the producer for adopting improved technology and for developing a production pattern broadly in the light of national requirements.

(ii) The need to ensure rational utilisation of land, water and other production resources.

(iii) The likely efft :t of the price policy o.i the rest of the economy, particularly an cost of living, ley©] of w -sosistructure, etc.

3. The Com
non-price measures as would facilituate the achievement of tiv
above.

4. To recommend from time to u respect of diff< i iltural co a measures necessary to make the price policy effective.

5. To take into account the changes in terms of trade betweea agricultural and non-cultural sectors.

6. To examine, where necessary, the prevailing methods and cost of marketing of agricultural commodities in different regions, suggest measures to reduce costs of marketing and recommend fair price margins tor different stages of marketing.

7. To keep ur.dcr review I he developing price situation and to make ap. Mieudations, as and when necessary, within the framework of the overall price policy.

8. To undertake studies i.i respect of different crops as may be prescribed rnraent from time to time.

'.. To keep under review studies relating to the price policy and tents for coBection of information regarding agricultural prices and Other telated data and suggest improvements in the same, and to organise research studies in the field of price policy.

10. To advise on any problems relating to agricul s and production that may be referred to - by Government from time to time.

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुये किसान

1513. श्री अजीत जोगी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुये हैं ;

(ख) क्या इस योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि से संबंधित दावों का अब तक निपटारा हो गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) इन दावों को कब तक निपटा लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ख) तथा (ग) जी हां । इस योजना का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गयी थी । समिति की सिफारिशों के आधार पर, योजना में निम्नलिखित आशोधन लागू किये गये :

(i) बीमा की गई राशि पूर्व में 150% की ऋण राशि की व्यवस्था की तुलना में कम करके फसल ऋण के 100% तक कर दी गई जो कि अधिकतम 10,000 रुपये प्रति कृषक है , और

(ii) उपज की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करते हुए क्षतिपूर्ति के विभिन्न स्तर शुरू किए गए ।

(घ) तथा (ङ) जी हां । खरीफ, 1993 मौसम के लिए उड़ीसा, गुजरात, पाण्डिचेरी और बिहार तथा रबी, 1993-94 मौसम हेतु आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़ सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सभी दावों का निपटारा किया गया । दावों के निपटारे में विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं :—

(i) उड़ीसा के मामले में फसल उपज संबंधी आंकड़ों का देर से प्रस्तुतीकरण, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के मामले में समय पर फसल उपज संबंधी आंकड़ों का प्रस्तुत न करना और पाण्डिचेरी के